

वशिव खाद्य सुरक्षा दविस, 2025

प्रलमिस के लयि:

[वशिव खाद्य सुरक्षा दविस](#), [भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधकिरण](#), [कोडेक्स एलीमेंटेरयिस कमीशन](#), [वशिव स्वासथय संगठन](#), [खाद्य और कृषि संगठन](#), [भारतीय पोषण रेटगि](#)

मेन्स के लयि:

खाद्य सुरक्षा वनियमन, खाद्य सुरक्षा बनाम खाद्य सुरक्षा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधकिरण, भारत में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ बनाना

[स्रोत: द हट्टि](#)

चरचा में कयों?

[वशिव खाद्य सुरक्षा दविस 2025](#) (7 जून), जसिका वषिय "फूड सेफटी: साइंस इन एक्शन" है, भारत की खाद्य मलिवट-केंद्रति प्रणाली से वज्जान आधारति खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की ओर बदलाव को उजागर करता है, जसि [भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधकिरण \(FSSAI\)](#) द्वारा संचालति कयि जा रहा है।

- प्रगतिके बावजूद, नयामक अंतराल और पुरानी प्रथाएँ अभी भी मौजूद हैं, जनिमें पुन: जाँच और सुधार की आवश्यकता है।
- **नोट:** वशिव खाद्य सुरक्षा दविस, जो [संयुक्त राष्ट्र महासभा](#) के प्रस्ताव के बाद 2019 से प्रतविरष 7 जून को मनाया जाता है, एक वैश्वकि अभियान है, जसिका उद्देश्य खाद्यजनति जोखमिों को रोकने, पहचानने और प्रबंधति करने के लयि जागरूकता बढ़ाना एवं कार्रवाई हेतु प्रेरति करना है।

भारत का खाद्य सुरक्षा ढाँचा कैसे वकिसति हुआ?

- **प्रारंभकि कानूनी ढाँचा (1954–2006):** खाद्य अपमशिरण नविरण अधनियम, 1954 ने खाद्य सुरक्षा को दवआधारी दृष्टकिण से देखा, जसिमें भोजन या तो मलिवटी था या नही, बनिा वभिनिन प्रकार के संदूषकों के बीच अंतर कयि या जोखमि के स्तर को ध्यान में रखे।
 - इसमें उपभोग की मात्रा, आहार संबंधी प्रवृत्तयिों या संदूषकों की भनिन-भनिन जोखमि रूपरेखाओं का ध्यान नही रखा गया था।
- **खाद्य सुरक्षा और मानक अधनियम, 2006 द्वारा सुधार:** इस अधनियम ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधकिरण (FSSAI) की स्थापना की, जसिसे भारत के मानकों को वैश्वकि मानकों के अनुरूप बनाया गया।
 - FSSAI ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं (**कोडेक्स एलीमेंटेरयिस**) के अनुरूप एक जोखमि-आधारति ढाँचा प्रस्तुत कयि, जसिमें कीटनाशकों के लयि अधिकितम अवशेष सीमा (MRL), खाद्य योजकों के लयि स्वीकार्य दैनिकि सेवन (ADI) तथा पशु औषधि अवशेषों और प्राकृतकि रूप से पाए जाने वाले वषिकत तत्त्वों के लयि मानक नरिधारति कयि गए।
 - वर्ष 2020 तक भारत के खाद्य सुरक्षा वनियम उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लगभग समकक्ष हो गए थे।

नोट: कोडेक्स एलीमेंटेरयिस, या "फूड कोड", मानकों, दशानरिदेशों और आचार संहतिओं का एक संग्रह है, जसि [कोडेक्स एलीमेंटेरयिस कमीशन \(CAC\)](#) द्वारा अपनाया गया है।

- कोडेक्स एलीमेंटेरयिस कमीशन (CAC) एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक संस्था है, जसिकी स्थापना वर्ष 1963 में [खाद्य और कृषि संगठन \(FAO\)](#) तथा [वशिव स्वासथय संगठन \(WHO\)](#) द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वासथय की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में नषिपक्ष प्रथाओं को सुनिश्चिति करना है। CAC के 189 सदस्य हैं और **भारत वर्ष 1964 में इस आयोग का सदस्य बना।**

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतयिों कयि हैं?

- **भारत-वशिष्ट वैज्जानकि आँकड़ों की कमी:** अधकिंश सुरक्षा मानक अंतर्राष्ट्रीय आँकड़ों पर आधारति होते हैं, जो भारतीय आहार पैटर्न, कृषि

- पद्धतियों या पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं।
- भारतीय पारंपरिक आहारों के माध्यम से संदूषकों के संचयी संपर्क का आकलन करने के लिये समग्र कुल आहार अध्ययन (TDS) का अभाव है।
 - स्थानीय विषयविज्ञान संबंधी अध्ययनों की कमी के कारण सटीक जोखिम आकलन में बाधा आती है।
 - अप्रभावी जोखिम संप्रेषण: MRL और ADI जैसे तकनीकी शब्द आम जनता के लिये समझने में कठिन होते हैं।
 - भारत में वर्तमान खाद्य लेबलिंग प्रणाली असंगत है और अक्सर समझने में कठिन होती है। फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (FOPL) को अनिवार्य न बनाए जाने के कारण उपभोक्ताओं के लिये किसी उत्पाद में उच्च मात्रा में नमक, चीनी या वसा की पहचान करना कठिन हो जाता है।
 - भारतीय पोषण रेटिंग (INR) अभी भी स्वैच्छिक है और इसमें उच्च स्टार रेटिंग के बावजूद पोषण गुणवत्ता नमिन होने की संभावना होती है, जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा सकता है।
 - वरिष्ठ और पुराने नियम: कुछ खाद्य नियम, जैसे- मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) से संबंधित, वैश्विक वैज्ञानिक सहमति के साथ टकराव रखते हैं।
 - MSG को JECFA द्वारा वर्ष 1971 से वैश्विक रूप से सुरक्षित माना गया है और कई देशों ने इसके चेतावनी लेबल हटा दिये हैं, लेकिन भारत अभी भी इसे शिशुओं के लिये असुरक्षित बताने वाला लेबल अनिवार्य करता है।
 - यह प्रतर्बंध वर्तमान वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। यह पुराना नियम उपभोक्ताओं को गुमराह करता है और पुराने नियमों को अद्यतन करने में भारत की अनिच्छा को दर्शाता है।
 - अनौपचारिक एवं अनियमित खाद्य क्षेत्र: भारत में खाद्य उत्पादन एवं वितरण का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक है, जिससे निगरानी करना कठिन हो जाता है।
 - स्ट्रीट फूड विक्रेता, छोटे खाद्य व्यवसाय और स्थानीय निर्माता अक्सर औपचारिक नियामक ढाँचे के बाहर कार्य करते हैं तथा उनमें स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता व अनुपालन का अभाव होता है।
 - उभरते खतरों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया: भारत रोगाणुरोधी प्रतिरक्षा (AMR), आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMO) या जलवायु-प्रेरित खाद्य खतरों जैसे उभरते खतरों के प्रति अनुकूलन में धीमा है।
 - प्रसंस्कृत और जंक फूड की बढ़ती खपत: प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर बढ़ता खर्च मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी गैर-संचारी रोग (NCD) को बढ़ावा दे रहा है।
 - अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में नमक, चीनी और वसा (HFSS) की मात्रा अधिक होती है, फरि भी इन्हें “स्वादपिष्ट” और “सस्ते” विकल्प के रूप में वर्णित किया जाता है।
 - भ्रामक वजिज्ञापन: फास्ट-मूविंग उपभोक्ता सामान कंपनियों आक्रामक और अक्सर भ्रामक वजिज्ञापनों का उपयोग करती हैं, विशेष रूप से बच्चों एवं परिवारों को लक्षित करके।
 - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी प्रथाओं पर चर्चा जताई है तथा इन्हें जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के उल्लंघन से जोड़ा है।

खाद्य सुरक्षा पर रिपोर्ट और सूचकांक

रिपोर्ट और सूचकांक	मुख्य अंतरदृष्टि
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (2023-2024) (FSSAI)	राज्यों के बीच व्यापक असमानता को दर्शाता है। केरल, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर तथा गुजरात मज़बूत खाद्य सुरक्षा उपायों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में अग्रणी हैं।
वर्ष में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2024	भारत में विश्व स्तर पर कुपोषित लोगों की सबसे बड़ी संख्या (194.6 मिलियन) है, हालाँकि यह वर्ष 2004-06 में 240 मिलियन से बेहतर है। 55.6% से अधिक भारतीय (790 मिलियन लोग) स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकते हैं, जो खराब खाद्य सामर्थ्य और पहुँच को दर्शाता है।
वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022	भारत को अलजीरिया के साथ 68वें स्थान पर रखा गया, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिये लगातार चुनौतियों और खतरों को दर्शाता है।

भारत में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये कनि सुधारों की आवश्यकता है?

- लेबलिंग और विनियामक ढाँचे को सुदृढ़ करना: जैसा कि FSSAI के मसौदा विनियमों (वर्ष 2022) और WHO द्वारा अनुशंसित किया गया है, अनिवार्य फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (FOPL) उपभोक्ताओं को त्वरित एवं सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकती है, विशेष रूप से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों HFSS के लिये।
 - FSSAI को HFSS खाद्य पदार्थों के लिये दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देना चाहिये, जिनमें अभी तक सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। एक स्पष्ट परिभाषा स्कूल कैंटीन और सार्वजनिक स्थानों पर लागू करने में सक्षम बनाएगी।
 - पोषण संबंधी आँकड़ों को सरल बनाने के लिये ट्रैफिक-लाइट लेबलिंग या न्यूट्री-स्कोर (जैसा कि यूरोप में उपयोग किया जाता है) जैसी स्टार रेटिंग अपनाएँ।
 - खाद्य, समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच साझा ज़िम्मेदारी शामिल है। सुरक्षा, स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य प्रणाली की दिशा में राष्ट्रव्यापी परिवर्तन हेतु केंद्र-राज्य समन्वय को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है।
- भ्रामक वजिज्ञापनों और स्वास्थ्य संबंधी दावों पर अंकुश लगाना: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत भ्रामक वजिज्ञापनों के खिलाफ [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] कार्रवाई करने हेतु FSSAI को सशक्त बनाना।
 - HFSS उत्पादों के सेलबिलिटी समर्थन पर प्रतर्बंध लगाएँ, विशेष रूप से उन पर, जो बच्चों को लक्षित करते हैं या प्रसंस्कृत उत्पादों को “स्वास्थ्य पेय” के रूप में गलत तरीके से बढ़ावा देते हैं।
- निगरानी, मॉनीटरिंग और अनुपालन में सुधार: खाद्य व्यवसायों द्वारा वास्तविक समय अनुपालन को ट्रैक करने के लिये INFoLNET (खाद्य

- अनौपचारिक क्षेत्र और स्ट्रीट फूड बिक्रेताओं को मुख्यधारा में लाना: [पीएम स्वच्छि](#) और [FSSAI](#) की ईट राइट स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत, बिक्रेताओं को स्वच्छता में प्रशिक्षण दिया गया है तथा "स्वच्छ स्ट्रीट फूड क्षेत्र" के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- व्यवसाय करने में आसानी के अंतर्गत FSSAI पंजीकरण को सरल बनाया जाएगा, वशेषरूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशीन जैसी योजनाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले सूक्ष्म उद्यमों और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिये।
- **स्वस्थ आहार और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना:** [पोषण अभियान](#), स्कूल पाठ्यक्रमों और डिजिटल इन्फ्लुएंसर का उपयोग कर स्वस्थ भोजन तथा पारंपरिक भारतीय आहार (जैसे- अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के दौरान कदन्न आधारित भोजन) को बढ़ावा देना चाहिए।
 - स्कूल परिसर और आस-पास के इलाकों में HFSS भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाले **स्कूल कैटीन दिशा-निर्देशों (2020)** का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना।
 - स्कूलों के लिये '[शुगर बोरड](#)' (जो खाद्य पदार्थों में शर्करा की मात्रा को प्रदर्शित करता है) लगाने का CBSE का आदेश बच्चों को जागरूक करने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है।
 - **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)** के आग्रह के अनुसार इसे राज्य और नजी स्कूलों तक भी वित्तारित किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा अवसरचना और भंडारण सुनिश्चित करना: शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिये कोल्ड स्टोरेज तथा सुरक्षा लॉजिस्टिक्स बनाने हेतु [पीएम किसान संपदा योजना](#) और [ऑपरेशन गरीन्स](#) जैसी योजनाओं का उपयोग करना चाहिए।
 - खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, वषिकृत पदार्थ एवं अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत सुरक्षा कीटनाशक तथा एंटीबायोटिक अवशेष सीमा को लागू करना।
- उभरते जोखिमों और स्वास्थ्य खतरों से निपटना: AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना के खाद्य सुरक्षा घटकों को वशेषरूप से पोल्ट्री, डेयरी और जलीय कृषि क्षेत्रों में लागू करना।

- **FSSAI खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम, 2006** के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। यह स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा पूरे देश में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- FSSAI के कार्यों में खाद्य वनियम बनाना, खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा कानूनों को लागू करना, खाद्य गुणवत्ता की निगरानी करना, जोखिम आकलन करना, खाद्य सुदृढीकरण और जैविक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना तथा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करना शामिल हैं।
- यह [वशिव खाद्य सुरक्षा दविस](#), [ईट राइट इंडिया](#), [ईट राइट स्टेशन](#), खाद्य सुरक्षा मतिर और [100 फूड स्ट्रीट](#) जैसे अभियान भी आयोजित करता है।
- **भोजन का अधिकार** भारतीय संवधान के अनुच्छेद 21 में नहित है, जो सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है। **अनुच्छेद 39(a) और 47** के साथ पढ़ने पर, यह राज्य को पर्याप्त आजीविका, पोषण और जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिये बाध्य करता है। यह अधिकार **अनुच्छेद 32** के माध्यम से एक मौलिक संवैधानिक उपाय के रूप में लागू किया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनिवार्यता और मौलिक अधिकार है। भारत को एक बहु-क्षेत्रीय, बहु-स्तरीय सुधार रणनीति की आवश्यकता है, जो न केवल उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करे, बल्कि उपभोक्ताओं को सशक्त भी बनाए। बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता और न्यायिक सक्रियता के साथ भारत की खाद्य प्रणाली को “पर्याप्त सुरक्षित” से “वास्तव में सुरक्षित और पौष्टिक” में बदलने का समय आ गया है।

प्रश्न: भारत में खाद्य सुरक्षा में क्या चुनौतियाँ हैं तथा वनियामक अनुपालन को मज़बूत करने के लिये नीतित्म सुधारों का सुझाव दीजिये।

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमश्रिण की रोकथाम (परविशन ऑफ फूड एडल्टरेशन) अधिनियम, 1954 को प्रतस्थापित किया।
2. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) (एफ.एस.एस.ए.आई.) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सवासथ्य सेवा महानदिशक के परभार में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (a)

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो “गरीबी रेखा से नीचे” (बी.पी.एल) श्रेणी में आते हैं।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत किये जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

?????:

प्रश्न. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को सविस्तार स्पष्ट कीजिये। (2019)